नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 225
दि. 19.05.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

शहनाइयों से चीखों तक: पालघर हाईवे हादसे ने उजाड़ दिए कई परिवार, बारातियों से भरे ट्रक की कंटेनर से भिड़ंत में 12 की मौत

पालघर। महाराष्ट्र के Palghar जिले में सोमवार तड़के हुआ एक भीषण सड़क हादसा कई परिवारों की जिंदगी पर ऐसा दर्द छोड़ गया, जिसे शायद कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। शादी की खुशियों और गीत-संगीत के बीच निकली एक बारात कुछ ही पलों में मातम में बदल गई। मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर कासा क्षेत्र के पास बारातियों से भरे एक छोटे ट्रक और तेज रफ्तार कंटेनर के बीच हुई भयावह टक्कर में 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में महिलाएं, बुजुर्ग और मासूम बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। हादसे की खबर फैलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और जिन घरों में शादी की तैयारियां चल रही थीं, वहां अचानक चीख-पुकार और मातम छा गया।

यह दर्दनाक दुर्घटना सोमवार तड़के लगभग चार बजे हुई, जब अधिकांश लोग नींद में थे और राजमार्ग पर हल्का कोहरा छाया हुआ था। पुलिस के अनुसार गुजरात की ओर जा रहा एक भारी कंटेनर अचानक अनियंत्रित हो गया और सामने से आ रहे आईशर ट्रक से जा भिड़ा। यह ट्रक बारातियों से भरा हुआ था और डहाणू तहसील के बापूगांव से शादी समारोह के लिए निकला था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन सड़क पर पलट गए और बारातियों से भरा ट्रक पूरी तरह चकनाचूर हो गया। कई लोग ट्रक के भीतर और उसके नीचे दब गए।

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि हादसे के बाद घटनास्थल पर भयावह दृश्य था। चारों ओर चीख-पुकार, घायल लोगों की कराह और बिखरे सामान दिखाई दे रहे थे। अंधेरे और

कोहरे के बीच स्थानीय लोगों ने सबसे पहले राहत कार्य शुरू किया। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर घायलों को बाहर निकालने का प्रयास किया और तुरंत पुलिस व आपदा राहत टीम को सूचना दी। कुछ ही देर में Maharashtra Police की कासा पुलिस टीम और हाईवे रेस्क्यू यूनिट मौके पर पहुंच गई। दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि राहत और बचाव कार्य में कई घंटे लग गए। क्रेन की मदद से दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सीधा किया गया और उनके नीचे दबे यात्रियों को बाहर निकाला गया। कई घायल ट्रक के लोहे के ढांचे में बुरी तरह फंस गए थे, जिन्हें गैस कटर की मदद से बाहर निकालना पड़ा। घायलों को तत्काल पास के कासा उप-जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने आपातकालीन इलाज शुरू किया। गंभीर रूप से घायल चार लोगों को बेहतर उपचार के लिए मुंबई और ठाणे के बड़े अस्पतालों में रेफर किया गया है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार कई घायलों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में दुर्घटना के पीछे कंटेनर चालक की तेज रफ्तार और लापरवाही को मुख्य कारण माना जा रहा है। अधिकारियों को आशंका है कि लंबे समय से वाहन चला रहे चालक को झपकी आ गई होगी, जिससे उसने वाहन पर नियंत्रण खो दिया। हादसे के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी के लिए दो विशेष टीमें गठित की गई हैं। आसपास के टोल प्लाजा और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपी चालक का पता लगाया जा सके।

इस भयावह हादसे के कारण मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात कई घंटों तक पूरी तरह प्रभावित रहा। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों और मलबे के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस और प्रशासन ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात को धीरे-धीरे सामान्य कराया। हादसे के दौरान सड़क पर मौजूद लोगों ने बताया कि दुर्घटना की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के गांवों तक सुनाई दी। कई लोग घरों से बाहर निकल आए और घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े।

शादी वाले परिवारों के लिए यह हादसा किसी भयानक सपने से कम नहीं रहा। जिन लोगों ने कुछ घंटे पहले तक खुशी-खुशी बारात को विदा किया था, उन्हें अचानक अपनों की मौत और घायल होने की खबर मिलने लगी। अस्पतालों और पुलिस थानों के बाहर परिजनों की भीड़ जमा हो गई। कई लोग अपने रिश्तेदारों को तलाशते नजर आए। मृतकों की पहचान होते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। कई परिवारों में एक से अधिक लोग हादसे का शिकार हुए हैं।

Government of Maharashtra ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके अलावा घायलों को 50-50 हजार रुपये की मदद और मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने अस्पतालों को घायलों के उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं।

राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। स्थानीय जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। कई सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवकों ने रक्तदान और राहत कार्य में सहयोग शुरू कर दिया है। वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन प्रभावी नियंत्रण के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है। हादसे में मारे गए लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और प्रशासन परिजनों को शव सौंपने की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर यह याद दिला दिया कि कुछ क्षणों की लापरवाही कैसे कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। जहां एक ओर शादी की खुशियां थीं, वहीं अब उन घरों में मातम पसरा है और हर आंख नम दिखाई दे रही है।

नॉर्डिक कूटनीति में भारत की बड़ी छलांग, नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री मोदी

ओस्लो। Narendra Modi को एक और बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। नॉर्वे सरकार ने भारतीय प्रधानमंत्री को अपने प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान 'द ग्रैंड क्रॉस' से सम्मानित किया है। यह सम्मान नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में गिना जाता है और इसे असाधारण वैश्विक योगदान, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग को नई दिशा देने के लिए प्रदान किया जाता है। इस सम्मान के साथ Narendra Modi को अब तक प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है, जो वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और प्रभाव को दर्शाता है।

'द ग्रैंड क्रॉस' नॉर्वेजियन रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट की सर्वोच्च श्रेणी मानी जाती है। यह सम्मान उन विशिष्ट वैश्विक नेताओं और हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय सहयोग, कूटनीतिक संबंधों और वैश्विक विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। नॉर्वे सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने, वैश्विक शांति, जलवायु सहयोग, हरित ऊर्जा और आर्थिक साझेदारी को नई गति देने के प्रयासों के लिए प्रदान किया है। Narendra Modi का यह नॉर्वे दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। यह उनकी पहली आधिकारिक नॉर्वे यात्रा है और पिछले 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का

भी यह पहला नॉर्वे दौरा है। राजधानी Oslo पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। नॉर्वे के प्रधानमंत्री Jonas Gahr Stre स्वयं हवाई अड्डे पर मौजूद रहे और उन्होंने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इस दौरान नॉर्वे सरकार के वरिष्ठ मंत्री और कई उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा केवल सम्मान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे भारत और नॉर्डिक देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। Narendra Modi और Jonas Gahr Stre 19 मई को Oslo में आयोजित तीसरे नॉर्डिक-भारत शिखर सम्मेलन में संयुक्त रूप से भाग लेने वाले हैं। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में भारत के साथ डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे जैसे नॉर्डिक देश भी शामिल होंगे।

यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़ती साझेदारी को और व्यापक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले पहला नॉर्डिक-भारत शिखर सम्मेलन वर्ष 2018 में Stockholm में आयोजित हुआ था, जबकि दूसरा सम्मेलन 2022 में Copenhagen में हुआ था। इन सम्मेलनों ने भारत और नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री सहयोग और डिजिटल विकास जैसे क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत आधार दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की साझेदारी का महत्व लगातार बढ़ रहा है। नॉर्डिक देश तकनीकी नवाचार, जलवायु नीति, हरित ऊर्जा और सतत विकास के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में गिने जाते हैं, जबकि भारत तेजी से उभरती वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच सहयोग वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा कर सकता है। Narendra Modi को मिले इस सम्मान को भारत की वैश्विक कूटनीतिक सफलता के रूप में भी देखा जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में उन्हें दुनिया के कई देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा गया है। इससे पहले उन्हें फ्रांस, रूस, अमेरिका, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ग्रीस, फिजी, पापुआ न्यू गिनी और कई अन्य देशों से भी प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रिय भूमिका, बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा और वैश्विक मुद्दों पर संतुलित नेतृत्व को इन सम्मानों की बड़ी वजह माना जाता है। नॉर्वे में भारतीय समुदाय के बीच भी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर खास उत्साह देखा गया। Oslo में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग उनका स्वागत करने पहुंचे। लोगों ने भारतीय तिरंगे और पारंपरिक नारों के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। प्रवासी भारतीयों ने इसे भारत के लिए गौरव का क्षण बताया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा केवल एक राजनयिक यात्रा नहीं, बल्कि भारत की बदलती वैश्विक भूमिका का प्रतीक भी है। नॉर्डिक देशों के साथ बढ़ता सहयोग यह संकेत देता है कि भारत अब पारंपरिक कूटनीतिक दायरे से आगे बढ़कर नए वैश्विक साझेदारों के साथ रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दे रहा है।

संसदीय मर्यादा पर सियासी संग्राम, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कांग्रेस ने खोला विशेषाधिकार मोर्चा

नई दिल्ली। संसद की गरिमा और संसदीय समितियों की भूमिका को लेकर सोमवार को राजनीति गरमा गई, जब Jairam Ramesh ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दाखिल किया। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संसद की स्थायी समिति को लेकर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण टिप्पणियां कीं, जिससे संसद की गरिमा और लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।

राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक Jairam Ramesh ने यह नोटिस राज्यसभा के सभापति C. P. Radhakrishnan को भेजा। नोटिस में उन्होंने कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 रद्द होने के बाद 15 मई को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में Dharmendra Pradhan ने शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के बारे में ऐसी टिप्पणियां कीं जो संसद के प्रति उनकी सोच और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने शिक्षा मंत्री से पूछा कि उनके मंत्रालय ने National Testing Agency यानी एनटीए को लेकर शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू क्यों नहीं किया। इस सवाल के जवाब में Dharmendra Pradhan ने कहा कि वह संसद की स्थायी समिति पर टिप्पणी नहीं करेंगे और केवल विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति यानी राधाकृष्णन समिति के बारे में बात करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि संसदीय स्थायी समिति में विपक्ष के सदस्य होते हैं और वे चीजों को "एक निश्चित तरीके से" लिखते हैं।

इसी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। Jairam Ramesh ने अपने नोटिस में कहा कि केंद्रीय मंत्री की यह टिप्पणी केवल विपक्षी सांसदों को निशाना बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संसद और उसकी समितियों की संस्थागत विश्वसनीयता पर भी हमला है। उन्होंने कहा कि संसदीय स्थायी समितियां संसद का विस्तारित स्वरूप होती हैं और इन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था में "मिनी संसद" माना जाता है। ऐसे में कार्यपालिका का विधायिका और उसकी समितियों के प्रति जवाबदेह होना भारतीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है।

कांग्रेस का आरोप है कि शिक्षा मंत्री की टिप्पणी से यह संदेश गया कि सरकार विपक्षी सदस्यों वाली संसदीय समितियों की सिफारिशों को गंभीरता से नहीं लेती। पार्टी नेताओं का कहना है कि संसद की स्थायी समितियां राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर नीतिगत सुझाव देने का काम करती हैं और उनकी सिफारिशों को इस तरह खारिज करना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब NEET-UG 2026 परीक्षा और पेपर लीक को लेकर पहले से ही राजनीतिक माहौल गर्म है। विपक्ष लगातार National Testing Agency की कार्यप्रणाली और शिक्षा मंत्रालय की जवाबदेही पर सवाल उठा रहा है। कई विपक्षी दलों ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की है। ऐसे में शिक्षा मंत्री की टिप्पणी ने विवाद को और बढ़ा दिया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला केवल एक बयान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संसद के आगामी सत्रों में भी जोरदार राजनीतिक टकराव का कारण बन सकता है। विशेषाधिकार हनन नोटिस को लेकर अब नजर राज्यसभा सभापति के अगले कदम पर टिकी हुई है। यदि नोटिस स्वीकार किया जाता है तो यह मामला विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जा सकता है, जहां इसकी जांच होगी। दूसरी ओर भाजपा नेताओं का कहना है कि मंत्री के बयान को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। पार्टी के कुछ नेताओं का दावा है कि Dharmendra Pradhan ने केवल यह कहा था कि वह तकनीकी और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर टिप्पणी करेंगे, न कि राजनीतिक दृष्टिकोण से तैयार रिपोर्ट पर। हालांकि कांग्रेस इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नजर नहीं आ रही है।

संसदीय लोकतंत्र में स्थायी समितियों की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ये समितियां विभिन्न मंत्रालयों और नीतियों की विस्तृत समीक्षा कर सरकार को सुझाव देती हैं। इनमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य शामिल होते हैं ताकि व्यापक विचार-विमर्श के बाद संतुलित सिफारिशें तैयार की जा सकें। यही वजह है कि संसदीय समितियों को संसद की कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। अब इस पूरे विवाद ने संसद, कार्यपालिका और संसदीय समितियों के संबंधों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। विपक्ष इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं के सम्मान का मुद्दा बना रहा है, जबकि सरकार इस विवाद को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगा रही है। आने वाले दिनों में यह मामला संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह सियासी गर्मी बढ़ा सकता है।

कोलकाता की सियासत में बड़ा बदलाव: 'शुभेंदु सरकार' के फैसलों से प्रशासनिक और सामाजिक नीतियों में नई दिशा की शुरुआत

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सोमवार को एक नए दौर की शुरुआत होती दिखाई दी, जब Suvendu Adhikari के नेतृत्व वाली सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में कई बड़े और दूरगामी प्रभाव वाले फैसले लिए। इन फैसलों ने राज्य की सामाजिक कल्याण नीतियों से लेकर प्रशासनिक ढांचे तक एक बड़े परिवर्तन के संकेत दे दिए हैं। बैठक के बाद राज्य सरकार की ओर से जो घोषणाएं सामने आईं, उन्होंने राजनीतिक हलकों में तीखी बहस छेड़ दी है और आने वाले समय में इनका असर राज्य की राजनीति और समाज दोनों पर देखने को मिल सकता है।

कैबिनेट बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला धार्मिक आधार पर चलाई जा रही सरकारी सहायता योजनाओं को समाप्त करने को लेकर लिया गया। सरकार ने घोषणा की कि अब राज्य में मदरसा विभाग और सूचना एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत धर्म आधारित किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता जारी नहीं रहेगी। इस निर्णय के साथ ही इमामों,

मुअज्जिनों और धार्मिक संस्थानों को दी जाने वाली मासिक सहायता योजनाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। पहले इन योजनाओं के तहत इमामों को लगभग 3000 रुपये और मुअज्जिनों को 1500 से 2000 रुपये तक मासिक सहायता दी जाती थी। सरकार का कहना है कि 1 जून 2026 से यह व्यवस्था पूरी तरह बंद कर दी जाएगी।

सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक समानता और धर्मनिरपेक्ष नीति के दृष्टिकोण से जोड़ा जा रहा है, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे राजनीतिक और सामाजिक रूप से विवादास्पद बताया है। वहीं सरकार का तर्क है कि सभी नागरिकों के लिए समान नीति अपनाना ही उसका लक्ष्य है और किसी भी प्रकार की धार्मिक वर्ग आधारित सहायता को समाप्त करना उसी दिशा में उठाया गया कदम है।

इसी कैबिनेट बैठक में राज्य की नई सामाजिक कल्याण योजनाओं की भी घोषणा की गई, जिनमें महिलाओं के लिए दो बड़ी योजनाएं शामिल हैं। सरकार ने 'अन्नपूर्णा योजना' को मंजूरी दी है, जिसके तहत 1 जून 2026 से राज्य की महिलाओं को प्रतिमाह 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना को राज्य की आर्थिक सशक्तिकरण नीति का हिस्सा बताया जा रहा है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए एक और बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य की सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की गई है।

इन दोनों योजनाओं को राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह सीधे तौर पर महिला मतदाताओं को प्रभावित करती हैं। पहले राज्य में Mamata Banerjee सरकार द्वारा 'लक्ष्मीर भंडार' योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता दी जाती थी। नई घोषणा के बाद यह राशि बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी गई है, जिसे राजनीतिक विश्लेषक एक बड़े चुनावी वादे के रूप में देख रहे हैं।

इसके अलावा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य सरकार के कर्मचारियों, शिक्षा बोर्ड और सरकारी संस्थानों में कार्यरत लाखों कर्मचारियों को भविष्य में वेतन संरचना में संशोधन का लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि, महंगाई भत्ते (DA) को लेकर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिसे लेकर कर्मचारियों में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है।

राज्य सरकार के इन फैसलों को लेकर प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि धार्मिक सहायता योजनाओं को समाप्त करना एक बड़ा नीतिगत बदलाव है, जिसका असर सामाजिक संतुलन और राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है। वहीं महिला केंद्रित योजनाओं को बढ़ावा देने का फैसला राज्य की सामाजिक नीति को एक नई दिशा देने का संकेत देता है।

कैबिनेट बैठक के बाद सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों की मंत्री Agnimitra Paul ने मीडिया को इन फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ अन्य सांस्कृतिक और धार्मिक अनुदानों पर अभी विचार जारी है और आगे और निर्णय लिए जा सकते हैं।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि Suvendu Adhikari के नेतृत्व में लिए गए ये फैसले राज्य की राजनीति में एक नई बहस को जन्म देंगे। जहां एक ओर समर्थक इसे सुधार और समानता की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, वहीं विरोधी इसे सामाजिक ढांचे में बड़े बदलाव के रूप में देख रहे हैं।

फिलहाल राज्य में इन फैसलों के बाद राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ गया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस की पूरी संभावना है।

संपादकीय

संवेदनशील विषयों पर अभिव्यक्ति में सतर्कता

इसमें दो राय नहीं कि देश के प्रतिष्ठित व शीर्ष पदों पर विराजमान व्यक्तियों को अपने संस्थानों व सार्वजनिक मंचों पर अपनी बात रखने में अतिरेक में सावधानी बरतनी चाहिए। उससे निकलने वाले शब्दों के अर्थों के कई मायने निकाले जा सकते हैं। ऐसी ही चर्चा देश की शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के हालिया बयानों को लेकर हुई। बताया जाता है कि एक अधिवक्ता द्वारा सीनियर का दर्जा दिए जाने के बाबत दायर याचिका पर खिन्न मुख्य न्यायाधीश ने प्रासंगिक संदर्भ में जो कहा, उसको लेकर सवाल उठे। बताया जा रहा है कि 'उन्होंने मौखिक तौर पर कहा कि समाज में पहले से ऐसे परजीवी हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं, और आप उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं... कुछ युवा ऐसे हैं, जो रोजगार नहीं मिलने और पेशे में जगह न बना पाने के कारण 'कॉकरोच' की तरह हर जगह फैल जाते हैं। उसमें से कुछ सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर हर किसी पर हमला शुरू कर देते हैं।' निश्चय ही हाल के वर्षों में संपादक विहीन सोशल मीडिया में लोगों के अराजक व्यवहार को देखते हुए यह भले ही यह सत्य न हो, कुछ लोग इसे अर्धसत्य बताते हैं। लेकिन न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति से इस विषय पर संवेदनशील ढंग से अभिव्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। हालांकि, बाद में जस्टिस सूर्यकांत ने 'कॉकरोच' वाले बयान पर कहा है कि 'मीडिया ने उनके शब्दों को गलत ढंग से पेश किया।'

उन्होंने अपनी मौखिक टिप्पणी के बाबत कहा कि उनकी बातों को इस तरह पेश किया गया जैसे उन्होंने देश के युवाओं की आलोचना की हो। उनका कथन था कि उनकी टिप्पणी केवल उन लोगों के खिलाफ थीं, जिन्होंने फर्जी या नकली डिग्रियों के सहारे वकालत जैसे पेशों में प्रवेश किया है। ऐसे ही लोग मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य सम्मानित पेशों में घुस आए हैं, इसलिए परजीवियों की तरह हैं। उनका इशारा न्यायापालिका पर होने वाले अनुचित हमलों की तरफ था। दरअसल, मुख्य न्यायाधीश ने वकीलों की कानून की डिग्रियों की जांच प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ वकीलों द्वारा डाली जाने वाली सामग्री को देखकर उन्हें कई वकीलों की कानूनी डिग्रियों की प्रमाणिकता पर संदेह है। लेकिन इसके साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों व सोशल एक्टिविस्ट ने सीजेआई की टिप्पणी को लेकर प्रतिक्रिया दी हैं। राज्यसभा में एक राजद सांसद ने सार्वजनिक चिट्ठी लिखकर मुख्य न्यायाधीश की भाषा को लेकर चिंता जतायी। उनका कहना था कि बेरोजगारों, आरटीआई कार्यकर्ताओं, मीडिया कर्मियों और असहमति व्यक्त करने वालों की तुलना 'कॉकरोच' व 'परजीवी' से करना लोकतंत्र की मूल आत्मा और उसकी बुनियादी संवैधानिक संस्कृति को आहत करने वाला लगता है। आलोचकों का कहना है कि न्यायपालिका से आशा की जाती है कि वह संवैधानिक संयम व गरिमा की अंतिम शरणस्थली बनी रहे। एक आरटीआई कार्यकर्ता का मानना है कि प्रश्न पूछने का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है, ये व्यवस्था पर हमला नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाये रखने में भूमिका है।

पंजाब कांग्रेस के लिए केरल से सबक लेना जरूरी

> राजनीति में त्वरित व स्पष्ट निर्णय लेने जरूरी होते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा न करके मौके चूक रही है। केरल विधानसभा चुनाव में बहुमत के बावजूद मुख्यमंत्री चयन में देरी और गुटबाजी दिखी। वहीं पंजाब में गुटों में बंटी कांग्रेस चुनावी तैयारी को लेकर राहुल गांधी के फ़ैसले का इंतजार कर रही है। शायद पंजाब कांग्रेस को केरल के सतीशन प्रसंग से सबक लेना चाहिए।

अच्छी-भली जीत को हार में बदलने का कांग्रेस पार्टी को मानो शौक ही है, राज्यों के हालिया विधानसभा चुनावों में यह काफी अच्छी तरह देखने को मिला; केरल में सबसे ज्यादा। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) का नेतृत्व करते हुए 140 विधायकों वाली विधानसभा में 102 सीटें जीत ज़बर्दस्त बहुमत पाने के बावजूद दस दिन लग गए मुख्यमंत्री तय करने में, आखिर ,छह बार के विधायक वी.डी. सतीशन को अपना 'मुख्यमंत्री-निर्वाचित' घोषित कर जनता के बीच और अधिक किरकिरी होने से बचाया।

यहां तक कि राहुल गांधी को भी यह अहसास हो गया था कि अपने सबसे खास सिपहसालार को 'ईश्वर के अपने देश' (केरल) में बतौर मुख्यमंत्री भेजना-यानी शक्तिशाली पार्टी महासचिव और संगठन प्रभारी के.सी. वेणुगोपाल को,जिन्हें इस पुरानी व बड़ी पार्टी के सबसे ताकतवर नेता के 'आंख-कान' कहा जाता है- केरल के लोगों को बिल्कुल रास नहीं आएगा। हां, अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा ही दिया जाता तो शायद लोग सुबह की कॉफी के साथ यह कड़वा घूंट निगल लेते। आखिरकार, जीतकर आए ज़्यादातर विधायक हफ्ता-दस दिन पहले तक वेणुगोपाल के ही खेमे में थे।

और फिर विरोध की आवाज़ें तेज़ होती गईं और माहौल बदल गया। लगता है कि वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने दखल दिया, जिससे निश्चित ही मदद मिली होगी। लेकिन असहमति का यह सुर दबा हुआ था- क्योंकि आखिर लोकसभा में विपक्ष के नेता के खिलाफ कौन खुलकर बोलने की हिम्मत करता? वह नेता जिसकी जियु-जित्सू मार्शल आर्ट की महारत, दुनिया के उनके नज़रिए का इतना अहम हिस्सा है, कि हाल ही में उन्होंने हिमाचल प्रदेश में संपन्न एक पार्टी कार्यक्रम के दौरान पंजाब कांग्रेस के नेताओं प्रताप बाजवा और राजा वड़िंग से दंड-बैठकें लगवा दीं; लेकिन उस खबर के लिए आपको मेरे सहयोगी राजमीत सिंह का लेख पढ़ना होगा- अंततः वडासेरी दामोदरन सतीशन के पक्ष में माहौल बन गया (उनके नाम का पहला भाग वडासेरी, जिसे थरावड भी कहते हैं, घर का नाम है, बीच वाला उनके पिता का नाम व आखिरी अंश उनका अपना नाम है)।

लेकिन ठीक उसी तरह, जैसे केरल के कांग्रेसी महिला व पुरुष गुरुवायूर में देवता के चरणों में नारियल फोड़ते हैं-विधायकों को सतीशन के पक्ष में झुकना पड़ा, इस तथ्य के मद्देनज़र कि अगले पांच साल तक उन्हें नहीं बल्कि राहुल गांधी को वेणुगोपाल से सीधे तौर पर बरतना है;साथ ही, दिल्ली में जो कुछ होता है, वह दिल्ली में ही रहना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता दत्तात्रेय होसबाले ने गत सप्ताह की शुरुआत में पाकिस्तान को लेकर सनसनीखेज बयान दिया कि : 'पुलवामा हमले जैसी 'छिटपुट घटनाओं' के बावजूद,लोगों के आपसी संवाद का अधिकाधिक मौका देकर कोशिश की जानी चाहिए। नागरिक स्तर के संबंध कारगर हो सकते हैं, क्योंकि हम एक ही राष्ट्र रहे हैं। देश की सुरक्षा और आत्म-सम्मान कायम रहे, लेकिन हमें दरवाज़े बंद करने की ज़रूरत नहीं। सदा उनसे संवाद को तैयार रहना चाहिए। व्यापार, वाणिज्य और वीज़ा जारी करना बंद न हो। बातचीत के लिए सदा खिड़की खुली रहे'। होसबाले ने यह साक्षात्कार न्यूज एजेंसी पीटीआई को ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के चंद दिन बाद दिया।

यह कथन कई कारणों से खास है। पहला,बतौर संघ 'सहकार्यवाह' यानी संगठन में दूसरे सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होसबाले एक शक्तिशाली नेता हैं, जिनके शब्दों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। दूसरा, यह इसका संकेत है कि आरएसएस समकालीन मुद्दों से लगातार जुड़ा रहता है। तीसरा, भले ही ये टिप्पणी सरकार की इस लीक से अलग हो कि 'आतंक और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते', फिर भी इस कथन को उस नीति की पुनर्समीक्षा की ज़मीन तैयार करने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। (फिलहाल, ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ) चौथा, ये साक्षात्कार न्यूज़ एजेंसी को दिया गया, जिससे संकेत मिलता है कि आरएसएस की मंशा थी कि साक्षात्कार बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंच सके। पांचवां, यह टिप्पणी होसबाले के अमेरिका से लौटने के तुरंत बाद आई है; वे शायद वहां कई तरह के लोगों से मिले होंगे, जिन्होंने उन्हें पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में बदलते वैश्विक परिदृश्य का बोध करवाया होगा-याद रहे, अमेरिका में आरएसएस की मज़बूत मौजूदगी है और वह भारतीय मूल के लोगों के एक बड़े तबके से गहराई से जुड़ा है। छठा, उनके कथन पर एक तरह से चुप्पी छाई रही, जिससे पता चलता है कि देश अभी भी उनके शब्दों का भार जज़्ब करने की कोशिश कर रहा है। सातवां, केवल पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज नरवाणे और जम्मू-कश्मीर के नेता फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने उनकी कही बात का स्वागत किया। फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने कहाः'अपनी समस्याएं सुलझाने को हमें सदा बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए'। आठवां, पाकिस्तान ने इन टिप्पणियों को 'सकारात्मक घटनाक्रम' बताया व उम्मीद जताई कि भारत में 'समझदारी' बनी रहेगी। निश्चित रूप से, पाकिस्तान को 'ऑपरेशन सिंदूर' से एक रणनीतिक सबक सीखना चाहिए -कि वह जब चाहे अपनी मर्ज़ी से, आतंकवाद का नल खोल या बंद नहीं कर सकता; कई दशकों से रावलपिंडी मुख्यालय में बैठे पाकिस्तानी फौजी जनरलों की साजिशों से भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। पंजाब से बेहतर यह कोई नहीं जानता; सीमावर्ती राज्य होने के नाते, पंजाब ने पाकिस्तान की उस रणनीति का सर्वाधिक खमियाज़ा भुगता, जिसके तहत वह 'हज़ार घाव देकर भारत को लहूलुहान करते रहने' की नीति जारी रखे है-अपनी सुविधानुसार आतंकवाद कभी गैंग-वाद का रूप धर लेता है, तो कभी जानलेवा नशीले पदार्थों की तस्करी का। ज़ाहिर है, पाकिस्तान को यह अहसास नहीं होने दिया जा सकता कि उसे बरी कर दिया गया, भले ही डोनाल्ड ट्रंप अपने 'पसंदीदा फील्ड मार्शल' को डोरे डाल रहे हों।

और गत सप्ताह की विडंबना यही रही-कि कांग्रेस, जो एक स्व-घोषित धर्मनिरपेक्ष संगठन है, उसने होसबाले के पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के कदम का स्वागत करने के बजाय टालमटोल वाली आलोचना की है। वहीं दूसरी ओर, आरएसएस, जो खुद को हिंदुत्व का स्वयंभू पैरोकार मानती है,'अखंड भारत' का तर्क देते हुए पाकिस्तान के मुसलमानों की ओर हाथ बढ़ा रही है, यह कहकर :'चूंकि हम एक राष्ट्र रहे हैं',लिहाजा हमें उनसे बातचीत करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। आप यह सवाल पूछ सकते हैंः कांग्रेस सही काम करने से इतना क्यों डरती है? केरल में वह किसी तरह खुद को बचा पाई, लेकिन तमिलनाडु में उसने अपने पुराने सहयोगी डीएमके को छोड़कर सत्ताधारी टीवीके से गठबंधन कर लिया-जबकि टीवीके को अब कांग्रेस की भी ज़रूरत नहीं रही, अब उसके पास भाजपा की पुरानी सहयोगी, किंतु अब अलग हो चुकी, एआईएडीएमके से टूटे एक गुट का समर्थन है। वहीं बंगाल में, उसने ममता बनर्जी की टीएमसी के विरुद्ध चुनाव लड़कर 'इंडिया' गठबंधन को भंग कर डाला- जिससे विपक्षी वोटों का बंटवारा हो गया- और यह सब सिर्फ़ इस खातिर कि टीएमसी की हार से राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं का मुंह बंद करा सकेंगे।

मेरी बात याद रखना—बदतर अभी आना बाकी है। पंजाब में, अब जबकि ज़्यादातर सियासी दल आगामी चुनावों के मद्देनज़र अपनी रणनीतियों को धार दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई गिरफ्तारियों, दलबदल और विलय रूपी रोज़-रोज़ के सियासी ड्रामे पर शायद ही कोई सार्थक ब्यान दिया हो- सिवाय इसके कि असमजंस में या फिर बेपरवाह नज़र आई; जबकि पार्टी के बड़े नेता शीर्ष पद के लिए आपस में लड़ रहे हैं।

पंजाब में गुटों में बंटी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के फ़ैसले का इंतज़ार कर रही है- कुछ संकट से नैया बचाने के इंतज़ार जैसा। शायद पंजाब कांग्रेस इकाई को केरल के सतीशन प्रसंग से सबक चाहिए; जैसा कि सी. गौरीदासन नायर लिखते हैं, सतीशन ने आंकड़ों पर आधारित अपनी बहसों से सियासी गलियारे के दोनों पक्षों से सम्मान अर्जित किया है-इसके अलावा उन्होंने लॉटरी माफ़िया के खिलाफ़ मुहिम चलाई और पश्चिमी घाट के पर्यावरण की रक्षार्थ पुरज़ोर आवाज़ उठाई।

प्रेरणा

व्यंग्य की चीरफाड़ में समाज का चेहरा

व्यंग्य को अक्सर हल्के साहित्य की तरह देखा जाता है, मानो उसका काम केवल मुस्कराहट पैदा करना हो। जबकि सच्चाई यह है कि व्यंग्य हंसी के भीतर छिपी बेचैनी का साहित्य है। वह उन सच्चाइयों को सामने लाता है, जिनसे समाज आंखें चुराता है। व्यंग्य की असली ताकत इसी में है कि वह सीधे प्रहार नहीं करता, बल्कि शब्दों के माध्यम से धीरे-धीरे भीतर उतरता है और पाठक को उसकी अपनी ही दुनिया का आईना दिखा देता है। अनिल सोनी का व्यंग्य संग्रह 'शव संवाद' इसी परंपरा का एक गंभीर और बेचैन करने वाला उदाहरण है। यह संग्रह केवल हंसाता नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना के उस जड़ हो चुके हिस्से को कुरेदता है, जो धीरे-धीरे संवेदनहीनता में बदलता जा रहा है।

'शव संवाद' नाम अपने आप में एक गहरी प्रतीकात्मकता लिए हुए है। शव यानी वह देह, जिसमें जीवन नहीं बचा, और संवाद यानी वह प्रक्रिया जिसमें विचारों का आदान-प्रदान होता है। जब इन दोनों शब्दों को साथ रखा जाता है तो यह हमारे समय की सबसे बड़ी विडंबना को सामने लाता है। समाज में संवाद तो बहुत हैं, बहसें भी हैं, शोर भी है, लेकिन चेतना कहीं मृतप्राय होती जा रही है। लोग बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पर भीतर का जीवंत मनुष्य लगातार खत्म होता जा रहा है। अनिल सोनी इसी मरे हुए सामाजिक विवेक को अपने व्यंग्य का विषय बनाते हैं।

उनकी लेखनी का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह सतही हास्य का सहारा नहीं लेती। वह किसी व्यक्ति विशेष पर कटाक्ष करने के बजाय पूरे सामाजिक ढांचे की परतें खोलती है। उनके व्यंग्य में जो बेचैनी है, वही उसे प्रभावशाली बनाती है। लेखक स्वयं लिखते हैं कि "व्यंग्य ने बुद्धिजीवी को कड़वाहट से भर दिया या वह व्यंग्य को कड़वा बना रहा है, इसी छटपटाहट का नाम है—शव संवाद।" यह पंक्ति केवल व्यंग्य की परिभाषा नहीं देती, बल्कि आज के बुद्धिजीवी वर्ग की स्थिति का भी संकेत करती है। वह वर्ग जो कभी समाज की दिशा तय करता था, आज खुद असमंजस और निष्क्रियता में फंसा दिखाई देता है।

अनिल सोनी ने अपने व्यंग्य में बुद्धिजीवी को केंद्र में रखकर जो बातें कही हैं, वे केवल साहित्यिक टिप्पणी नहीं बल्कि सामाजिक यथार्थ का दस्तावेज हैं। जब वे लिखते हैं कि "सही सोचना भी सपना लगता है", तब वे उस दौर की ओर इशारा करते हैं जहां सच बोलना कठिन ही नहीं, बल्कि अव्यावहारिक माना जाने लगा है। आज का समाज सुविधाओं और तात्कालिक लाभों के बीच इस तरह उलझ गया है कि सामूहिक सपनों की जगह व्यक्तिगत सुरक्षा ने ले ली है। हर व्यक्ति बस इतना चाहता है कि वह किसी तरह बचकर निकल जाए। संघर्ष, प्रतिरोध और परिवर्तन जैसे शब्द धीरे-धीरे केवल भाषणों और पुस्तकों तक सीमित होते जा रहे हैं।

यह व्यंग्य संग्रह हमारे मीडिया और जनचेतना पर भी तीखा सवाल उठाता है। लेखक का यह कथन कि "भारत में व्यस्तता के दो कारण हैं—या तो मनोरंजन में व्यस्त हैं या किसी त्रासदी से भी व्यस्त हो सकते हैं" आज के समाज की भयावह सच्चाई को उजागर करता है। टीवी चैनलों और सोशल मीडिया ने त्रासदियों को भी एक तमाशे में बदल दिया है। किसी दुर्घटना, हिंसा या राजनीतिक विवाद पर घंटों बहस होती है, लोग उसमें डूबे रहते हैं, पर कुछ समय बाद वही मुद्दा गायब हो जाता है और उसकी जगह नया शोर ले लेता है। संवेदनाएं स्थायी नहीं रहीं, वे उपभोग की वस्तु बन चुकी हैं। लोग दुख को महसूस नहीं करते, उसे केवल देखते हैं, जैसे किसी मनोरंजन कार्यक्रम को देख रहे हों।

'शव संवाद' की एक और बड़ी विशेषता यह है कि उसमें प्रतीकों का बेहद प्रभावशाली प्रयोग हुआ है। पोस्टर वाला प्रसंग इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। लेखक लिखते हैं कि पोस्टर बुद्धिजीवी से कहीं आगे निकल गए, जबकि बुद्धिजीवी वहीं का वहीं खड़ा रह गया। यह केवल राजनीतिक पोस्टरों की बात नहीं है। यह उन तमाम नारों, अभियानों और दिखावटी आंदोलनों की ओर संकेत है, जो समाज में लगातार उभरते रहते हैं। असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और प्रतीक आगे निकल जाते हैं। विचार की जगह प्रचार ले लेता है। बुद्धिजीवी सोचता रह जाता है और समाज नारेबाजी में बहता चला जाता है। अनिल सोनी का व्यंग्य इसलिए अलग दिखाई देता है क्योंकि वह केवल व्यवस्था पर हमला नहीं करता, बल्कि पाठक को भी कठघरे में खड़ा करता है। वह यह एहसास कराता है कि विसंगतियां केवल नेताओं, संस्थाओं या मीडिया में नहीं हैं, वे हमारे भीतर भी हैं। हम भी धीरे-धीरे संवेदनहीन होते जा रहे हैं। हम अन्याय देखकर चुप रह जाते हैं, झूठ को जानते हुए भी स्वीकार कर लेते हैं और सुविधाओं के बदले अपने विवेक से समझौता कर लेते हैं। यही कारण है कि यह व्यंग्य संग्रह पढ़ते समय पाठक केवल हंसता नहीं, भीतर कहीं असहज भी होता है। व्यंग्य की सबसे बड़ी सफलता यही होती है कि वह पाठक को उसकी सहज स्थिति से बाहर निकाल दे। 'शव संवाद' यह काम पूरी शक्ति के साथ करता है। इसमें हास्य है, लेकिन वह हल्कापन पैदा करने वाला हास्य नहीं है। वह ऐसा हास्य है, जिसके बाद मन में एक कड़वाहट और बेचैनी रह जाती है। यही बेचैनी पाठक को सोचने पर मजबूर करती है। यही साहित्य का असली उद्देश्य भी है।

आज जब साहित्य का एक बड़ा हिस्सा मनोरंजन और त्वरित लोकप्रियता की ओर बढ़ रहा है, ऐसे समय में 'शव संवाद' जैसे व्यंग्य संग्रह महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि साहित्य केवल समय बिताने की चीज नहीं, बल्कि समाज की आत्मा को झकझोरने का माध्यम भी है। अनिल सोनी ने अपने व्यंग्य के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि व्यंग्यकार कोई मसखरा नहीं होता, बल्कि वह समाज का सबसे बेचैन और सजग व्यक्ति होता है। वह उन दरारों को देखता है, जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। 'शव संवाद' अंततः हमारे समय का दस्तावेज बनकर उभरता है। यह उस समाज की कहानी है, जो संवाद तो कर रहा है, लेकिन भीतर से धीरे-धीरे जड़ होता जा रहा है। यह संग्रह बताता है कि विसंगतियों पर प्रहार केवल साहित्यिक कर्म नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। अनिल सोनी का व्यंग्य पाठक को हंसाने से ज्यादा उसे भीतर तक विचलित करता है और शायद यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।

यूरोप की कट्टरपंथी लहर ने ब्रिटेन में दस्तक देते हुए कैसे राजनीति में मचा दिया भूचाल, PM स्टार्मर की चली जाएगी कुर्सी?

ब्रिटेन की राजनीति में इस समय बड़ा भूचाल देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को लेकर इस्तीफे की अटकलें और तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबर पार्टी के अंदर बढ़ते दबाव और खराब राजनीतिक माहौल के कारण स्टार्मर अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि वह सम्मानजनक तरीके से पद छोड़ने की रणनीति बना रहे हैं। इस बीच लेबर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य सचिव वैस स्ट्रिंग के बयान ने ब्रिटिश राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। वैस ने खुलकर कहा है कि ब्रेग्जिट यानी यूरोपियन संघ से अलग होना ब्रिटेन की बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ब्रिटेन को दोबारा यूरोपियन संघ के करीब जाना होगा। उनके मुताबिक ब्रिटेन का भविष्य यूरोप से जुड़ा हुआ है और एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब ब्रिटेन फिर से यूरोपियन संघ में शामिल हो जाए। स्ट्रिंग के इस बयान के बाद लेबर पार्टी के अंदर सत्ता संघर्ष की चर्चा तेज होगी। माना जा रहा है कि अगर स्टारमर इस्तीफा देते हैं तो वैस खुद पार्टी नेतृत्व की दौड़ में उतर सकते हैं। वहीं स्टार्मर की मुश्किलें हाल ही में सामने आई। जेफरी एपस्टिन विवाद के बाद और बढ़ गई। रिपोट्र्स में दावा किया गया कि लेबर पार्टी से जुड़े कुछ नेताओं के एब्सस्टीन से संबंध की जानकारी पहले से ही मौजूद थी। हालांकि इस मामले में कोई आधिकारिक आरोप साबित नहीं हुआ है। लेकिन विपक्ष लगातार सरकार और पार्टी पर सवाल उठा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लेबर पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन होता है और यूरोप समर्थक नेता मजबूत होते हैं तो ब्रिटेन और यूरोपियन संघ के रिश्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 12 मई को कैबिनेट मीटिंग के दौरान स्टार्मर रिजाइन करने से मना कर दिया है। इसके बाद स्टार्मर सरकार के एक जूनियर मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। कुछ सहयोगी भी पहले ही सरकार छोड़ चुके हैं। अब 80 से ज्यादा लेबर सांसद खुलकर यह मांग कर चुके हैं कि कीर स्टार्मर अपने इस्तीफे की तारीख तय करें ताकि पार्टी व्यवस्थित तरीके से अपना नया नेता चुन सके। ऐसे में पहला बड़ा सवाल तो यही है कि 2 साल पहले ही इतनी बड़ी बहुमत के साथ जीतकर 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचे स्टारमर पर अब कुर्सी छिनने का खतरा क्यों मंडरा रहा है? ब्रिटेन में हाल ही में हुए लोकल चुनाव में लेबर पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। पार्टी ने स्थानीय परिषदों में 1400 से ज्यादा सीटें गवा दी। वेल्स में भी दशकों बाद उसे बड़ी हार मिली। वहीं रिफॉर्म यूके पार्टी ने कई जगह जीत दर्ज की। जबकि उसे कुल वोटों का 30% से भी कम हिस्सा मिला था। नतीजे आने के बाद स्टारमर ने 11 मई को एक भाषण भी दिया। बिना टाई और जैकेट के सफेद शर्ट पहनकर मंच पर आए स्टारमर ने इमोशनल अंदाज में अपनी गलतियों पर अफसोस जताया। हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने लेबर पार्टी के मूल्यों को दोहराया। स्टारमर और उनके समर्थकों ने दलील दी कि अगर लीडरशिप बदला गया तो देश में राजनीतिक अराजकता फैल सकती है। उन्होंने याद दिलाया कि 204 में लेबर पार्टी की जीत से पहले कंजर्वेटिव पार्टी में लगातार प्रधानमंत्री बदलते रहे थे। लेकिन उनकी इस स्पीच का पार्टी सांसदों पर कोई असर नहीं दिखा। कई सांसदों का मानना है कि जनता के बीच स्टारमर की गिरती लोकप्रियता की वजह से लेबर पार्टी को ऐतिहासिक हार झेलनी पड़ी। पार्टी नगर परिषदों की सीटें हार गई। स्कॉटलैंड और वेल्स की संसदों में भी खराब प्रदर्शन हुआ।

इसे भी पढ़ेंः रूस ने यूक्रेन के 2 ड्रोन को रोका, कोई हताहत नहीं हुआ

14 साल बाद 2024 में लेबर पार्टी को इंग्लैंड के चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। कीर ने सांसद बनने के मात्र 9 साल के भीतर प्रधानमंत्री पद तक का सफर पूरा किया। ब्रिटेन के 50 साल के इतिहास में पहले व्यक्ति थे जो 60 की उम्र के बाद पीएम बने। स्टार्मर खुद को नास्तिक कहते हैं, लेकिन पत्नी की यहूदी मान्यताओं का पूरा सम्मान करते हैं। ब्रिटेन को 'क्लीन एनर्जी सुपरपावर' बनाने का लक्ष्य रखा है। 'ग्रेट ब्रिटिश एनर्जी' कंपनी बनाएंगे। कीर कहते हैं फुटबॉल के मैदान पर वे न 'सर' होते हैं न ही नेता। वे आम इंसान बन जाते हैं। यूनिवर्सिटी लाइफ में दक्षिण फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा इलाके में आइसक्रीम बेचकर पैसा कमाने का सोचा। पुलिस ने आइसक्रीम जब्त की कर ली। पब्लिक प्रॉसिक्यूशन के डायरेक्टर पद के दौरान वे नियमों और डिटेल को लेकर इतने सख्त थे कि साथियों ने उन्हें मि. रूल्स नाम दे दिया था।

स्टार्मर की घटती पॉपुलैरिटी ये जो है इसकी वजह सिर्फ लोकल इलेक्शंस नहीं है। पिछले कई महीनों से स्टार्मर की स्थिति कमजोर होती जा रही है। वे खराब अर्थव्यवस्था, अवैध प्रवास को लेकर जनता की नाराजगी झेल रहे हैं। अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत रहे पीटर मैडलसन की नियुक्ति भी विवाद बन गई थी। पिछले सितंबर ब्रिटिश मीडिया ने मेंडिलसन और जेफरी एपस्टीन की बातचीत के कई ईमेल्स शेयर किए थे। जिसके बाद उन्हें पद से हटाना पड़ा था। इसके बाद मेंडलसन पर आरोप लगे कि उन्होंने 2006 2007 के वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान एपस्टीन के साथ वित्तीय बाजारों से जुड़ी सेंसिटिव जानकारी साझा की थी। कीर स्टारमर पर आरोप लगा कि उन्होंने वार्निंग्स को नजरअंदाज किया और एपस्टीन से मेंडलसन के रिश्तों की जानकारी होने के बावजूद उन्हें राजदूत बना दिया। बवाल के बाद स्टार्मर ने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें यह नहीं पता था कि मेंडलसन और एपस्टीन इतने करीब थे।

अभियान

जब सोना सिर्फ आभूषण नहीं, बेटी के सम्मान और आत्मनिर्भरता की पहचान था

भारतीय सभ्यता और संस्कृति में विवाह केवल दो लोगों का साथ नहीं माना गया, बल्कि यह दो परिवारों, दो संस्कृतियों और दो जीवन यात्राओं का मिलन समझा गया है। यही कारण है कि भारतीय शादियों में हर रस्म, हर परंपरा और हर प्रतीक का अपना विशेष महत्व होता है। इन परंपराओं में सोने का स्थान सबसे अलग और सबसे स्थायी रहा है। सदियों से भारतीय परिवार बेटी की शादी में सोना देने को केवल एक सामाजिक रस्म नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, सुरक्षा और प्रेम का प्रतीक मानते आए हैं। दुल्हन के गहनों की चमक में केवल सौंदर्य नहीं होता, बल्कि उसके पीछे परिवार की चिंता, भविष्य की सुरक्षा और भावनाओं की पूरी दुनिया छिपी होती है।

आज के आधुनिक दौर में भले ही शादी के तौर-तरीके बदल गए हों, फैशन बदल गया हो, लेकिन भारतीय विवाहों में सोने की अहमियत आज भी वैसी ही बनी हुई है। इसका कारण केवल इसकी आर्थिक कीमत नहीं, बल्कि वह सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व है जो भारतीय समाज ने सदियों से सोने को दिया है। दादी-नानी की पीढ़ी हमेशा कहा करती थी कि "बेटी का असली सहारा उसका सोना होता है।" यह वाक्य केवल परंपरागत सोच नहीं था, बल्कि जीवन के अनुभवों से निकली हुई गहरी समझ थी। उस समय महिलाओं के पास आर्थिक स्वतंत्रता बहुत कम होती थी। वे नौकरी या व्यापार से जुड़ी नहीं होती थीं और उनका जीवन अधिकतर परिवार पर निर्भर रहता था। ऐसे समय में शादी में मिला सोना ही उनका सबसे बड़ा निजी संबल माना जाता था।

भारतीय समाज में शादी के समय बेटी को दिए गए गहनों को "स्त्रीधन" कहा गया। स्त्रीधन का अर्थ केवल धन या संपत्ति नहीं था, बल्कि यह महिला के अधिकार और सम्मान का प्रतीक माना जाता था। धर्मशास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि विवाह के समय मिले गहनों और उपहारों पर केवल महिला का अधिकार होता है। यह उसकी निजी संपत्ति होती थी, जिसे किसी और से जोड़ा नहीं जाता था। यदि जीवन में कभी आर्थिक संकट आता, परिवार पर कठिन समय पड़ता या पति की आय रुक जाती, तो यही सोना सबसे पहले काम आता था। कई परिवारों में मुश्किल परिस्थितियों में महिलाओं ने अपने गहने बेचकर या गिरवी रखकर पूरे घर को संभाला। यही वजह है कि पुराने समय में सोने को केवल श्रृंगार नहीं, बल्कि सुरक्षा कवच माना जाता था। भारतीय संस्कृति में सोने का धार्मिक महत्व भी बेहद गहरा है। सोने को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि सोना घर में समृद्धि, सुख और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। यही कारण है कि शादी के समय दुल्हन को सोने के गहनों से सजाने की परंपरा लगभग पूरे भारत में दिखाई देती है। जब नई दुल्हन अपने ससुराल में प्रवेश करती है, तो उसे केवल परिवार की नई सदस्य नहीं माना जाता, बल्कि घर की लक्ष्मी समझा जाता है। उसके शरीर पर सजे सोने के गहने इस बात का प्रतीक होते हैं कि वह अपने साथ खुशहाली और सौभाग्य लेकर आई है।

भारत के अलग-अलग राज्यों और समुदायों में सोने के गहनों की अपनी अलग पहचान है। दक्षिण भारत में मंदिर जूलरी और लंबे हार दुल्हन के श्रृंगार का अहम हिस्सा होते हैं। राजस्थान और गुजरात में भारी कंगन, बोरला और नथ को शान का प्रतीक माना जाता है। बंगाल में पारंपरिक सोने के हार और चूड़ियां विवाह की पहचान मानी जाती हैं। पंजाब की दुल्हन के गहनों में शाही अंदाज दिखाई देता है। महाराष्ट्र में ठुशी और नथ का विशेष महत्व है। हर क्षेत्र में गहनों की डिजाइन और शैली बदल जाती है, लेकिन सोने की अहमियत समान बनी रहती है। यह विविधता भारतीय संस्कृति की गहराई और उसकी खूबसूरती को दर्शाती है।

सोने का महत्व केवल उसकी चमक या कीमत में नहीं है, बल्कि उसमें जुड़ी भावनाओं में भी है। भारतीय परिवारों में गहने पीढ़ियों तक संभालकर रखने की परंपरा रही है। दादी की चूड़ियां, मां का हार या नानी की नथ केवल गहने नहीं होते, बल्कि वे परिवार की यादों और रिश्तों की विरासत बन जाते हैं। कई बार एक ही गहना तीन-चार पीढ़ियों तक चलता है। जब कोई मां अपनी बेटी को वही हार पहनाती है जो उसे उसकी मां से मिला था, तब वह केवल एक आभूषण नहीं सौंपती, बल्कि परिवार की स्मृतियां, संस्कार और आशीर्वाद भी सौंपती है। यही भावनात्मक जुड़ाव भारतीय समाज में सोने को विशेष बना देता है।

समय के साथ महिलाओं की स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं और अपने फैसले खुद लेने में सक्षम हैं। इसके बावजूद शादी में सोने की परंपरा समाप्त नहीं हुई। बल्कि अब इसका स्वरूप थोड़ा बदल गया है। पहले जहां सोना केवल सुरक्षा और परंपरा का प्रतीक था, वहीं अब इसे निवेश और आर्थिक स्थिरता के रूप में भी देखा जाता है। लोग मानते हैं कि सोना सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक है। इसकी कीमत समय के साथ बढ़ती रहती है और जरूरत पड़ने पर इसे आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है। यही वजह है कि आज भी कई परिवार बेटी के जन्म के साथ ही उसके लिए थोड़ा-थोड़ा सोना जमा करना शुरू कर देते हैं।

हालांकि इस परंपरा का एक दूसरा पक्ष भी है। समय के साथ कई जगहों पर सोने और दहेज की होड़ ने सामाजिक समस्या का रूप ले लिया। समाज में दिखावे और प्रतिष्ठा की दौड़ ने शादी को कई परिवारों के लिए आर्थिक बोझ बना दिया। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर अधिक गहने देने का दबाव बढ़ा। लेकिन यदि इस परंपरा के मूल भाव को समझा जाए तो उसका उद्देश्य कभी दिखावा नहीं था। इसका उद्देश्य बेटी को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाना था। दादी-नानी की सोच में सोना बेटी के लिए सम्मान और सुरक्षा का माध्यम था, न कि समाज को प्रभावित करने का साधन।

भारतीय शादियों में सोने का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। दुल्हन के लिए उसके गहने केवल सजावट नहीं होते, बल्कि वे आत्मविश्वास और भावनात्मक सुरक्षा का एहसास भी देते हैं। शादी के दिन जब वह पारंपरिक गहनों से सजी होती है, तो उसके भीतर एक अलग प्रकार का गौरव महसूस होता है। परिवार के लिए भी यह गर्व का क्षण होता है कि वे अपनी बेटी को पूरे सम्मान और प्रेम के साथ विदा कर रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय परिवारों में शादी के गहनों को लेकर इतनी भावनात्मक तैयारी होती है।

आज फैशन की दुनिया तेजी से बदल रही है। डायमंड, प्लेटिनम और हल्की डिजाइनर जूलरी का चलन बढ़ गया है। इसके बावजूद गोल्ड जूलरी का आकर्षण कम नहीं हुआ। भारतीय दुल्हन चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों न हो, उसके विवाह के श्रृंगार में सोने की मौजूदगी किसी न किसी रूप में जरूर दिखाई देती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सोना भारतीय मानसिकता और संस्कृति में गहराई से जुड़ा हुआ है। यह केवल धातु नहीं, बल्कि विश्वास और स्थायित्व का प्रतीक बन चुका है। भारतीय समाज में सोने को शुभता से भी जोड़ा गया है। अक्षय तृतीया, धनतेरस और दिवाली जैसे अवसरों पर सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। लोगों का विश्वास है कि सोना घर में स्थिरता और समृद्धि लाता है। यही भावना शादी के समय और अधिक गहरी हो जाती है। दुल्हन का सोने से सजा होना केवल उसकी सुंदरता नहीं बढ़ाता, बल्कि यह भी दर्शाता है कि वह अपने नए जीवन की शुरुआत शुभता और सौभाग्य के साथ कर रही है।

मां-बाप के लिए बेटी को सोना देना केवल एक परंपरा निभाना नहीं होता, बल्कि यह उनके प्रेम और चिंता की अभिव्यक्ति भी होती है। जब एक मां अपनी बेटी को गले का हार पहनाती है या पिता उसके लिए गहने बनवाता है, तो उसमें केवल धन खर्च नहीं होता, बल्कि उसके भीतर यह भावना छिपी होती है कि उनकी बेटी जीवन के हर मोड़ पर सुरक्षित और सम्मानित रहे। यही कारण है कि भारतीय परिवारों में सोने को लेकर भावनात्मक जुड़ाव इतना गहरा है।

समाज चाहे जितना आधुनिक हो जाए, तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन भारतीय विवाहों में सोने की परंपरा इसलिए जीवित है क्योंकि यह केवल फैशन या सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय नहीं, बल्कि रिश्तों, विश्वास और पीढ़ियों की भावनाओं का हिस्सा है। सोना यहां केवल गहना नहीं, बल्कि परिवार की स्मृतियों, संस्कारों और बेटी के भविष्य की सुरक्षा का प्रतीक बन चुका है।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

ओबीसी आरक्षण से लेकर 2400 मेगावाट ऊर्जा परियोजना तक योगी कैबिनेट के बड़े फैसले, पंचायत चुनावों से लेकर स्वास्थ्य और मेट्रो तक विकास की नई दिशा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति और विकास एजेंडा को नया आकार देते हुए मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े और दूरगामी फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण निर्धारण से लेकर ऊर्जा उत्पादन, स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार और मेट्रो परियोजनाओं तक कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं।

बैठक में सबसे अहम निर्णय पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण को लेकर लिया गया। सरकार ने इसके लिए "उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग" के गठन को मंजूरी दी है। यह आयोग राज्य में पंचायत स्तर पर आरक्षण की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करेगा और उसके आधार पर नई सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

यह आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप काम करेगा और छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। आयोग का नेतृत्व एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे, जबकि कुल पांच सदस्य इसके हिस्से होंगे।

इस फैसले को ग्रामीण राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पंचायत चुनावों में आरक्षण का सीधा असर गांवों की सत्ता संरचना पर पड़ता है।

वित्त मंत्री Suresh Kumar Khanna ने बैठक के बाद जानकारी दी कि आयोग ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर ओबीसी आबादी, उनके प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भागीदारी का विस्तृत अध्ययन करेगा। इसके आधार पर ही आरक्षण की नई अनुशंसाएं तय होंगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पंचायतों में ओबीसी आरक्षण किसी भी स्थिति में 27 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह प्रावधान सामाजिक संतुलन और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप रखा गया है।

बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा एक बड़ा फैसला भी लिया गया। लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के गोमतीनगर विस्तार परिसर में 1010 बेड का अत्याधुनिक मल्टी-स्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर बनाने को मंजूरी दी गई।

यह परियोजना लगभग 855.04 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जाएगी और इसमें एक नया ओपीडी ब्लॉक तथा 200 सीट क्षमता वाला टीचिंग ब्लॉक भी शामिल होगा। इस कदम से लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का बड़ा विस्तार होने की उम्मीद है।

Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences को इस परियोजना से सुपर स्पेशलिटी और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में बड़ा लाभ मिलने वाला है।

ऊर्जा क्षेत्र में भी सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मीरजापुर में 3x800 मेगावाट क्षमता की कुल 2400 मेगावाट की तापीय ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 38,358 करोड़ रुपये है।

यह परियोजना राज्य सरकार और एनटीपीसी के संयुक्त उपक्रम के रूप में विकसित की जाएगी। इससे उत्तर प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और भविष्य की ऊर्जा मांगों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

इस परियोजना से न केवल औद्योगिक क्षेत्रों को स्थिर बिजली आपूर्ति मिलेगी, बल्कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है।

शहरी विकास के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने अहम कदम उठाया है। लखनऊ मेट्रो के फेज-1बी (चारबाग-वसंतकुंज ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर) के लिए केंद्र, राज्य सरकार और यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बीच त्रिपक्षीय समझौते को मंजूरी दी गई।

इस परियोजना पर लगभग 5801.05 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसमें केंद्र और राज्य सरकार की बराबर हिस्सेदारी होगी। यह कॉरिडोर लखनऊ की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक मजबूत और आधुनिक बनाएगा।

इसके अलावा पशुपालन क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण निर्णय में वेटरनरी छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते को 4000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। यह कदम पशु चिकित्सा शिक्षा को प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बैठक में आगरा मेट्रो कॉरिडोर-2 के लिए भूमि हस्तांतरण, स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के विस्तार, उत्तर प्रदेश जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली-2026, मीरजापुर ट्रांसमिशन लाइन परियोजना और सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी की स्थापना जैसे कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

इन सभी फैसलों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार का फोकस एक साथ कई क्षेत्रों—शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा और शहरी विकास—को मजबूत करने पर है। Yogi Adityanath के नेतृत्व में यह कैबिनेट बैठक आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की विकास दिशा को और अधिक गति देने वाली मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऊर्जा परियोजनाएं राज्य की औद्योगिक वृद्धि को गति देंगी, जबकि स्वास्थ्य और मेट्रो परियोजनाएं शहरी जीवन स्तर को बेहतर बनाएंगी। वहीं पंचायत आरक्षण आयोग का गठन ग्रामीण लोकतंत्र में पारदर्शिता और संतुलन लाने का प्रयास है। कुल मिलाकर, यह कैबिनेट बैठक उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल को बहुआयामी दिशा देने वाली साबित हो सकती है, जिसमें सामाजिक न्याय से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक हर क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई है।

तेजस परमार के सूरत कलेक्टर बनने से प्रशासन में नई ऊर्जा विकास कार्यों और जनहित योजनाओं पर रहेगा विशेष फोकस

सूरत। गुजरात के तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक और शहरी केंद्र सूरत जिले को एक नया प्रशासनिक नेतृत्व मिला है। राज्य सरकार द्वारा किए गए हालिया आईएएस फेरबदल के तहत 2016 बैच के अधिकारी Tejas Parmar ने सोमवार, 18 मई को सूरत के नए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के रूप में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। उनके कार्यभार संभालने के साथ ही जिले के प्रशासनिक तंत्र में नई ऊर्जा और नई प्राथमिकताओं की चर्चा तेज हो गई है।

पदभार ग्रहण समारोह सूरत कलेक्टर कार्यालय में आयोजित किया गया, जहां वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, विभिन्न विभागों के प्रमुखों, कर्मचारियों और शहर के कई गणमान्य नागरिकों ने उनका स्वागत किया। पुष्पगुच्छ भेंट कर नए कलेक्टर का अभिनंदन किया गया और जिले के प्रशासनिक भविष्य को लेकर शुभकामनाएं दी गईं।

इस अवसर पर प्रशासनिक माहौल में औपचारिकता के साथ-साथ उम्मीदों का भी एक स्पष्ट संकेत देखने को मिला, क्योंकि सूरत जैसे तेज गति से बढ़ते शहरी क्षेत्र में कलेक्टर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

नए कलेक्टर Tejas Parmar ने पदभार संभालते ही अधिकारियों के साथ एक परिचयात्मक बैठक की। इस बैठक में जिले की भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक ढांचे, चल रहे विकास कार्यों और प्रमुख सरकारी योजनाओं की प्रारंभिक समीक्षा की गई। उन्होंने विभागवार रिपोर्टों को समझा और अधिकारियों से जमीनी स्तर की स्थिति पर विस्तृत जानकारी ली।

बैठक में मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि विकास कार्यों की गति को और तेज किया जाए तथा जिन परियोजनाओं में देरी हो रही है, उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। इसके साथ ही जनहित से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित निपटारे और प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई।

Tejas Parmar ने स्पष्ट संकेत दिया कि उनका प्रशासनिक दृष्टिकोण जनकेंद्रित रहेगा और सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिक प्राथमिकता होगी।

सूरत जैसे शहर में जहां औद्योगिक विकास, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि तेज गति से हो रही है, वहां प्रशासनिक संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती माना जाता है। ऐसे में नए कलेक्टर से यह अपेक्षा की जा रही है कि वे विकास और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेंगे।

नए कलेक्टर का शैक्षणिक और प्रशासनिक अनुभव भी इस जिम्मेदारी को और महत्वपूर्ण बनाता है। Tejas Parmar मूल रूप से बनासकांठा जिले के पालनपुर से आते हैं। उन्होंने सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (SVNIT) से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि होने के कारण उन्हें तकनीकी दृष्टिकोण और प्रशासनिक विश्लेषण दोनों में दक्ष माना जाता है।

उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 310वीं रैंक प्राप्त कर प्रशासनिक सेवा में प्रवेश किया था। यह उपलब्धि उनके समर्पण और मेहनत का प्रमाण मानी जाती है।

अपने करियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है। दाहोद में असिस्टेंट कलेक्टर, अमरेली में जिला विकास अधिकारी, गांधीनगर में अर्बन डेवलपमेंट विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी, मध्य गुजरात बिजली कंपनी लिमिटेड में मैनेजिंग डायरेक्टर और जूनागढ़ नगर निगम में म्युनिसिपल कमिश्नर जैसे पदों पर काम करते हुए उन्होंने शासन और प्रशासन दोनों स्तरों पर अनुभव अर्जित किया है।

इन विविध भूमिकाओं ने उन्हें ग्रामीण विकास से लेकर शहरी प्रशासन तक की गहरी समझ प्रदान की है, जो सूरत जैसे बहुआयामी जिले के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो सकती है।

पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में Tejas Parmar ने कहा कि सूरत जैसे तेज गति से विकसित हो रहे शहर में प्रशासनिक टीम का हिस्सा बनना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना होगी कि सभी सरकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू हों और नागरिकों को समय पर सेवाएं मिलें।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाएगा, ताकि नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।

सूरत जिले में वर्तमान में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, शहरी विकास योजनाएं, सड़क और परिवहन सुधार कार्यक्रम तथा सामाजिक कल्याण योजनाएं चल रही हैं। नए कलेक्टर के सामने इन सभी कार्यों को गति देने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होगी।

अधिकारियों के बीच यह भी चर्चा है कि नए कलेक्टर विकास परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान देंगे और प्रत्येक विभाग की प्रगति रिपोर्ट को डिजिटल सिस्टम के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा।

इसके अलावा, जन शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने और शहरी इलाकों में नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर भी विशेष फोकस रहने की उम्मीद है।

सूरत एक औद्योगिक हब होने के कारण यहां डायमंड, टेक्सटाइल और व्यापारिक गतिविधियों का विशाल नेटवर्क मौजूद है। ऐसे में प्रशासनिक फैसलों का सीधा असर लाखों लोगों के जीवन और रोजगार पर पड़ता है। इस कारण कलेक्टर की भूमिका केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

नए कलेक्टर Tejas Parmar ने यह संकेत दिया है कि वे पूर्व प्रशासन द्वारा शुरू किए गए जनहित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और उन्हें और प्रभावी बनाने की दिशा में काम करेंगे।

स्थानीय लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों में यह उम्मीद देखी जा रही है कि नए नेतृत्व में सूरत जिले में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और सरकारी योजनाएं अधिक प्रभावी तरीके से लागू होंगी।

एआई ट्रेडिंग पर कड़े नियम लाने की तैयारी में सेबी, जल्द जारी होगी नई गाइडलाइन; भारतीय बाजार झटकों के बावजूद मजबूत

भुवनेश्वर। वैश्विक वित्तीय बाजारों में बढ़ती अनिश्चितता और तकनीकी बदलावों के बीच भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बड़ा संकेत दिया है कि वह जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित ट्रेडिंग के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा। यह घोषणा सेबी के चेयरमैन Tuhin Kanta Pandey ने सोमवार को भुवनेश्वर में आयोजित एक निवेशक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान की।

उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक हालात, विशेष रूप से पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ी है, लेकिन भारतीय शेयर बाजार में इस तरह के बाहरी झटकों को झेलने की मजबूत क्षमता मौजूद है।

Tuhin Kanta Pandey ने कहा कि आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था अत्यधिक आपस में जुड़ी हुई है। किसी भी क्षेत्र में उत्पन्न संकट का प्रभाव दूसरे देशों के बाजारों पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पश्चिम एशिया में तनाव के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है, जिससे वैश्विक स्तर पर कीमतों और महंगाई के जोखिम में वृद्धि हुई है।

इस स्थिति का सीधा असर ऊर्जा बाजारों पर देखा जा रहा है, जहां कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव बढ़ गया है। होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण मार्गों पर बाधा आने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव और भी बढ़ गया है।

हालांकि, Tuhin Kanta Pandey ने स्पष्ट किया कि इन सभी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय पूंजी बाजार अपेक्षाकृत स्थिर और लचीला बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय बाजारों की संरचना मजबूत है और वे विभिन्न प्रकार के आर्थिक झटकों को सहन करने में सक्षम हैं।

अपने संबोधन में उन्होंने विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बताया कि सेबी अब ट्रेडिंग और निवेश से जुड़े क्षेत्रों में एआई के उपयोग को लेकर एक व्यापक नियामक ढांचा (framework) तैयार कर रहा है। यह गाइडलाइन जल्द ही जारी की जाएगी।

Tuhin Kanta Pandey ने कहा कि एआई वित्तीय क्षेत्र के लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि यह डेटा विश्लेषण, जोखिम मूल्यांकन और ट्रेडिंग रणनीतियों को अधिक तेज और प्रभावी बनाता है। लेकिन इसके साथ ही यह तकनीक कुछ गंभीर जोखिम भी लेकर आती है, जिनमें साइबर सुरक्षा, डेटा हेरफेर और एल्गोरिदमिक गलतियों की संभावना शामिल है।

उन्होंने कहा कि यदि एआई का उपयोग अनियंत्रित रूप से किया गया तो यह बाजार में अस्थिरता पैदा कर सकता है। इसलिए सेबी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तकनीक का उपयोग पारदर्शिता, सुरक्षा और निवेशक हितों को ध्यान में रखकर किया जाए।

सेबी प्रमुख ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग और हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग पर निगरानी और कड़ी की जा सकती है, ताकि छोटे निवेशकों के हित सुरक्षित रह सकें। उन्होंने कहा कि भारत का पूंजी बाजार तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें घरेलू तथा विदेशी निवेशकों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में नियामक ढांचे का आधुनिक और तकनीक-सक्षम होना बेहद जरूरी है।

कार्यक्रम के दौरान निवेशकों को जागरूक करते हुए उन्होंने कहा कि बाजार में उतार-चढ़ाव सामान्य प्रक्रिया है और निवेशकों को दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अफवाहों और अस्थिर वैश्विक घटनाओं के आधार पर निर्णय लेने से बचना चाहिए।

Tuhin Kanta Pandey ने यह भी कहा कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों की परस्पर निर्भरता बढ़ने से किसी भी क्षेत्र में उत्पन्न संकट का असर तेजी से अन्य देशों तक पहुंचता है। इसलिए निवेशकों को वैश्विक परिस्थितियों पर भी नजर रखनी चाहिए।

विशेषज्ञों का मानना है कि सेबी द्वारा एआई गाइडलाइन लाने का यह कदम भारतीय शेयर बाजार को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

भारत में डिजिटल ट्रेडिंग और ऑनलाइन निवेश प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में एआई आधारित सिस्टम का उपयोग भी बढ़ रहा है। इस संदर्भ में नियामक हस्तक्षेप समय की आवश्यकता माना जा रहा है।

सेबी का यह प्रस्तावित फ्रेमवर्क न केवल बड़े संस्थागत निवेशकों बल्कि छोटे रिटेल निवेशकों की सुरक्षा को भी मजबूत करेगा।

कुल मिलाकर, Tuhin Kanta Pandey की यह घोषणा संकेत देती है कि भारतीय पूंजी बाजार अब तकनीकी क्रांति के नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जहां एआई के उपयोग को नियंत्रित और संतुलित तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि नवाचार और सुरक्षा दोनों के बीच सही संतुलन बना रहे।

भारत–ओमान एफटीए से खुलेंगे निर्यात के नए द्वार: आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिलेगी वैश्विक रफ्तार

नई दिल्ली। भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति को नई दिशा देने वाला एक ऐतिहासिक कदम जल्द ही लागू होने जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री Piyush Goyal ने घोषणा की है कि भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA) एक जून से लागू हो जाएगा। इस समझौते के लागू होते ही भारतीय निर्यातकों के लिए मध्य पूर्व के बाजारों में बड़े अवसर खुलेंगे और देश की अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक पहुंच पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगी।

यह समझौता ऐसे समय में लागू हो रहा है जब भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी स्थिति को लगातार मजबूत कर रहा है और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को गति दे रहा है। सरकार का मानना है कि यह एफटीए भारत के निर्यात आधारित विकास मॉडल को मजबूती देगा और छोटे से लेकर बड़े उद्योगों तक सभी को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

भारत और ओमान के बीच यह समझौता केवल व्यापारिक करार नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक आर्थिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जा रहा है। इससे दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान आसान होगा, टैरिफ बाधाएं कम होंगी और व्यापार की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी।

केंद्रीय मंत्री Piyush Goyal ने कहा कि इस एफटीए से भारत के निर्यातकों को विशेष रूप से कपड़ा, इंजीनियरिंग उत्पाद, ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि उत्पाद, रसायन और आईटी सेवाओं जैसे क्षेत्रों में बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल घरेलू खपत पर आधारित अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि एक मजबूत निर्यात आधारित वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

सरकार ने अगले पांच वर्षों में 2 ट्रिलियन डॉलर निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। यह लक्ष्य केवल आर्थिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह भारत को वैश्विक व्यापार में शीर्ष देशों की श्रेणी में स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा है। इसके लिए सरकार लगातार नए व्यापार समझौते, नीतिगत सुधार और उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है।

नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय व्यापारिक सम्मेलन में बोलते हुए Piyush Goyal ने स्पष्ट कहा कि भारत को आयात पर निर्भरता कम करनी होगी और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने कहा कि यदि 140 करोड़ भारतीय 'वोकल फॉर लोकल' को अपनाते हैं, तो भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता।

इस सम्मेलन का आयोजन Confederation of All India Traders (CAIT) और India Trade Promotion Organisation (ITPO) के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इसमें देशभर के व्यापारी, उद्योग प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स, महिला उद्यमी और नीति विशेषज्ञ शामिल हुए।

कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि भारत अब वैश्विक व्यापार व्यवस्था में एक निर्णायक भूमिका निभाने की ओर बढ़ रहा है। सरकार की नीति स्पष्ट है कि घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती हासिल की जा सकती है। इसी दिशा में 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को केंद्र में रखा गया है।

Piyush Goyal ने कहा कि यदि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनना है तो उसे अपने स्थानीय उद्योगों को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक यदि भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता देगा, तो इससे रोजगार, उत्पादन और निर्यात तीनों में तेजी आएगी।

इस अवसर पर सरकार ने यह भी बताया कि भारत व्यापार महोत्सव नामक एक बड़े आयोजन की तैयारी की जा रही है, जो 12 से 15 अगस्त तक भारत मंडपम में आयोजित होगा। यह आयोजन देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME), महिला उद्यमियों और युवाओं को वैश्विक मंच देने का एक बड़ा प्रयास होगा।

इस महोत्सव का उद्देश्य 'वोकल फॉर लोकल' को 'लोकल टू ग्लोबल' में बदलना है। इसमें लगभग 1000 व्यवसाय अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। सरकार का मानना है कि इससे भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता, ब्रांडिंग और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उनकी पहुंच को मजबूती मिलेगी।

इस आयोजन में लॉजिस्टिक्स कंपनियों, परिवहन संगठनों, स्वदेशी जागरण मंच और लघु उद्योग भारती जैसी संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह पूरा इकोसिस्टम भारतीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने में मदद करेगा।

एफटीए के लागू होने से भारत के छोटे और मध्यम निर्यातकों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। ओमान जैसे बाजारों में भारतीय उत्पादों की मांग पहले से ही मजबूत रही है, और अब टैरिफ कम होने से भारतीय सामान अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध हो सकेंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता भारत के लिए मध्य पूर्व और अफ्रीका के बाजारों में प्रवेश को आसान बनाएगा। ओमान रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है, जो खाड़ी देशों और अफ्रीका के बीच व्यापार का द्वार माना जाता है। ऐसे में भारत की पहुंच इन क्षेत्रों तक और मजबूत होगी।

इस समझौते का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे सेवा क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। आईटी, हेल्थकेयर, एजुकेशन और कंसल्टिंग जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए नए अवसर खुलेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, और इस तरह के व्यापार समझौते इसे और मजबूती प्रदान करेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि भारत को न केवल उत्पादन केंद्र बनाया जाए, बल्कि उसे वैश्विक निर्यात हब के रूप में भी स्थापित किया जाए।

Piyush Goyal ने यह भी कहा कि आने वाले वर्षों में भारत का ध्यान केवल बड़े उद्योगों पर नहीं, बल्कि छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स को भी वैश्विक मंच देने पर होगा। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ताकत उसकी विशाल घरेलू मांग और विविध उत्पादन क्षमता में निहित है। यदि इसे सही दिशा दी जाए, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देशों में शामिल हो सकता है।

सरकार का मानना है कि यह एफटीए केवल आर्थिक समझौता नहीं है, बल्कि यह भारत की वैश्विक भूमिका को पुनर्परिभाषित करने वाला कदम है। इससे न केवल व्यापार बढ़ेगा, बल्कि भारत और ओमान के बीच रणनीतिक संबंध भी मजबूत होंगे।

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि आने वाले समय में भारत कई अन्य देशों के साथ भी इसी तरह के व्यापार समझौते करेगा, जिससे वैश्विक व्यापार में उसकी हिस्सेदारी और बढ़ेगी।

कुल मिलाकर, एक जून से लागू होने वाला भारत–ओमान एफटीए भारत की आर्थिक नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है। यह समझौता न केवल निर्यात को गति देगा, बल्कि 'आत्मनिर्भर भारत' और 'विकसित भारत' के लक्ष्य को भी मजबूत आधार प्रदान करेगा।

पश्चिम रेलवे के 14 कर्मचारियों को महाप्रबंधक,संरक्षा पुरस्कार से किया गया सम्मानित

मुंबई सेंट्रल, वडोदरा, अहमदाबाद एवं भावनगर मंडलों के कर्मचारियों को महाप्रबंधक संरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय द्वारा मार्च 2026 के लिए 14 कर्मचारियों को महाप्रबंधक "मैन ऑफ द मंथ" संरक्षा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह सम्मान पश्चिम रेलवे मुख्यालय, मुंबई में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। इन कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट सतर्कता, कर्तव्यनिष्ठा एवं समर्पण के लिए सम्मानित किया गया, जिससे संभावित अप्रिय घटनाओं को रोकने तथा सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला। सम्मानित कर्मचारियों में मुंबई सेंट्रल मंडल से 5, अहमदाबाद मंडल से 4, वडोदरा मंडल से 3 तथा भावनगर मंडल से 2 कर्मचारी शामिल थे।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुंबई सेंट्रल मंडल के पांच कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान उनकी उत्कृष्ट सतर्कता एवं त्वरित कार्रवाई के लिए सम्मानित किया गया। उनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

ट्रेन मैनेजर श्री अजय कुमार शिवशंकर प्रसाद ने ट्रेन का चार्ज लेते समय असाधारण सतर्कता का परिचय दिया। उन्होंने एक वैगन के नीचे पहिये की असामान्य स्थिति देखी, जो ट्रेन परिचालन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती थी तथा जिससे पटरी से उतरने की आशंका थी। उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की गई। उनकी समय पर दी गई सूचना एवं सतर्कता से संभावित दुर्घटना टल गई तथा सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित हुआ।

वरिष्ठ ट्रेन मैनेजर (पैसेंजर) श्री विनोद कुमार को भरूच स्टेशन पर ट्रेन संख्या 69172 भरूच–सूरत मेमू में ड्यूटी के दौरान उनकी सूझबूझ के लिए सम्मानित किया गया। ट्रेन के प्रस्थान के समय उन्होंने एक 70 वर्षीय यात्री को चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते समय घिसटते हुए देखा। श्री विनोद कुमार ने तुरंत गार्ड इमरजेंसी ब्रेक लगाया तथा मोटरमैन को सतर्क किया, जिससे ट्रेन तुरंत रुक गई और यात्री को सुरक्षित बचा लिया गया। उनकी त्वरित कार्रवाई से संभावित जनहानि टल गई तथा यात्री सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा गया।

पॉइंट्समैन श्री भरत आई. पटेल को भी उनकी सतर्कता एवं त्वरित कार्रवाई के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने रेल फ्रैक्चर का पता चलते ही तुरंत ड्यूटी पर मौजूद स्टेशन अधीक्षक को सूचित किया। उस समय कर्णावती एक्सप्रेस स्टेशन की ओर आ रही थी, जिसे उत्राण स्टेशन पर रोका गया। इंजीनियरिंग कर्मचारियों द्वारा ट्रैक की मरम्मत की गई तथा गति प्रतिबंध के साथ ट्रेन परिचालन बहाल किया गया। उनकी समय पर की गई कार्रवाई एवं संरक्षा के प्रति सजगता से एक बड़ी अप्रिय घटना टल गई।

सहायक खलासी श्री मधुबन यादव को वसई रोड स्टेशन पर एक ट्रेन की रोलिंग-इन जांच के दौरान उनकी असाधारण सतर्कता एवं सजगता के लिए सम्मानित किया गया। ड्यूटी के दौरान उन्होंने ट्रेन के कई वैगनों में लोडेड एचआर कॉयल्स की लाशिंग टूटी हुई एवं अनुचित पाई। इस दोष की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दी गई तथा आवश्यक कार्रवाई की गई। उनकी त्वरित पहचान एवं समय पर दी गई सूचना से संभावित दुर्घटना टल गई तथा सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित हुआ। उनकी सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता एवं संरक्षा चेतना की सराहना की गई।

वरिष्ठ सहायक लोको पायलट श्री लोकेश मीणा को भी परिचालन संरक्षा के प्रति असाधारण सतर्कता एवं समर्पण प्रदर्शित करने के लिए सम्मानित किया गया। वे ट्रेन संख्या 14707 रणकपुर एक्सप्रेस में सूरत से दादर के मध्य कार्यरत थे। सूरत स्टेशन पर लोकोमोटिव निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि पावर कार के हेड-ऑन जनरेशन सिस्टम का इंटर व्हीक्यूलर कपलर खुल गया था और खतरनाक रूप से ट्रैक पर लटक रहा था, जिससे ट्रेन परिचालन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने तुरंत लोको पायलट एवं पावर कार स्टाफ को सूचित किया, जिसके बाद तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई कर दोष को दूर किया गया। उनकी असाधारण सतर्कता, सूझबूझ एवं समय पर की गई कार्रवाई से संभावित गंभीर दुर्घटना टल गई तथा सुरक्षित एवं निर्बाध रेल परिचालन सुनिश्चित हुआ।

वडोदरा, अहमदाबाद एवं भावनगर मंडलों के कर्मचारियों को भी रेल फ्रैक्चर, ट्रैक में अनियमितताओं आदि जैसे संरक्षा संबंधी खतरों की समय पर पहचान एवं निराकरण के लिए सम्मानित किया गया। उनकी त्वरित कार्रवाई ने सम्पूर्ण नेटवर्क पर सुरक्षित रेल परिचालन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

पश्चिम रेलवे सभी सम्मानित कर्मचारियों के कर्तव्य के प्रति समर्पण, व्यावसायिकता एवं सुदृढ़ संरक्षा चेतना की सराहना करता है। इनके सराहनीय कार्यों से न केवल संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सका, बल्कि सुरक्षित एवं विश्वसनीय रेल परिचालन के प्रति पश्चिम रेलवे की अटूट प्रतिबद्धता और सुदृढ़ हुई है। साथ ही, ये कर्मचारी अन्य रेलकर्मियों के लिए प्रेरणास्रोत बने हैं।

भीषण गर्मी में यात्रियों को राहत: भावनगर मंडल के जूनागढ़ स्टेशन पर निःशुल्क छाछ का वितरण

भीषण गर्मी एवं बढ़ते तापमान के मद्देनज़र यात्रियों को राहत प्रदान करने हेतु पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा जनहित में विशेष पहल की गई है। इस क्रम में शुक्रवार को जूनागढ़ रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए निःशुल्क छाछ वितरण की व्यवस्था की गई।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि जूनागढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म क्षेत्र में यात्रियों विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं बच्चों को छाछ उपलब्ध कराया गया, जिससे उन्हें भीषण गर्मी से काफी राहत मिली।

निःशुल्क छाछ वितरण सेवा में "आयुष हॉस्पिटल-जूनागढ़" का सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ। "आयुष हॉस्पिटल-जूनागढ़"ने यात्रियों के लिए निःशुल्क 200 लीटर छाछ की व्यवस्था की।

स्टेशन पर इन व्यवस्थाओं को सफलतापूर्वक संचालित करने में भावनगर मंडल के वाणिज्य विभाग के निरीक्षकों, टिकट चेकिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई तथा वितरण कार्य को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न किया।

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक (DRM) श्री दिनेश वर्मा ने कहा, "भीषण गर्मी के दौरान यात्रियों को राहत प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भावनगर मंडल द्वारा विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से इस प्रकार की जनहितकारी गतिविधियाँ निरंतर आयोजित की जा रही हैं। यह पहल हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता एवं यात्री-हित के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है।"

भावनगर मंडल द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं मानवीय सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती रहें। भीषण गर्मी के दौरान इस प्रकार की राहत सेवाएँ आगे भी निरंतर जारी रहेंगी।

विश्व पर्यावरण दिवस 2026" के तहत मंडल रेल प्रबंधक ने दिलाई पर्यावरण संरक्षण की शपथ

भारतीय रेल द्वारा 15 मई से 5 जून 2026 तक आयोजित किए जा रहे विश्व पर्यावरण दिवस अभियान के तहत 18 मई 2026 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, अहमदाबाद में एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक (DRM) श्री वेद प्रकाश ने मंडल कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता तथा प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन के प्रति प्रतिज्ञा दिलाई। शपथ के माध्यम से सभी उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पर्यावरण संरक्षण को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने, जल एवं ऊर्जा की बचत करने, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, स्वच्छता बनाए रखने तथा हरित एवं सतत जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया।

इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक प्रदूषण में कमी, स्वच्छता, जल एवं ऊर्जा संरक्षण तथा सतत जीवनशैली को बढ़ावा देना है। इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न रेलवे स्टेशनों, रेलवे कॉलोनियों, कार्यालय परिसरों एवं सार्वजनिक स्थलों पर प्रभात फेरियां, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, कार्यशालाएं, जागरूकता रैलियां, प्रतियोगिताएं तथा सामाजिक सहभागिता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

15 मई से 5 जून 2026 तक चलने वाले इस विशेष अभियान के दौरान रेलवे परिसरों, पटरियों एवं जल स्रोतों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे। साथ ही "एक पेड़ मां के नाम" पहल के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। "सिंगल यूज़ प्लास्टिक" के उपयोग को कम करने तथा पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए विशेष जन-जागरूकता अभियान संचालित किए जाएंगे। यात्रियों को डिजिटल टिकटिंग अपनाने, पुनः उपयोग योग्य पानी की बोतलों तथा कपड़े एवं जूट के बैगों के उपयोग हेतु प्रेरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नुक्कड़ नाटक, कार्यशालाओं, जागरूकता रैलियों, प्रतियोगिताओं एवं सामाजिक सहभागिता कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा।

5 जून 2026 को "विश्व पर्यावरण दिवस" के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा।

मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने कहा कि पश्चिम रेलवे का अहमदाबाद मंडल पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निरंतर आगे बढ़ाते हुए समाज में पर्यावरण जागरूकता फैलाने हेतु सतत कार्य करता रहेगा। उन्होंने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण को जन-आंदोलन बनाने तथा स्वच्छ एवं हरित भारत के निर्माण में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से गुजरात कैडर में आवंटित 2025 बैच के 8 प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारियों ने मुलाकात की

बावन सप्ताह के जिला प्रशिक्षण से पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को शुभकामनाएं दीं

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के साथ सोमवार को गुजरात कैडर में आवंटित 2025 की भारतीय सिविल सेवा बैच के 8 प्रोबेशनरी अधिकारियों ने गांधीनगर में शिष्टाचार मुलाकात की।

ये प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी में फाउंडेशन कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण करके गुजरात कैडर में सहायक कलेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं। उन्हें बावन सप्ताह के जिला प्रशिक्षण के लिए बनासकांठा, भरूच, अमरेली, कच्छ, पंचमहल, गोधरा, वलसाड, राजकोट और महीसागर जिले आवंटित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मुलाकात के दौरान प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए सामान्य नागरिक तथा वंचित गरीबों के कल्याण के सेवा संकल्प के साथ सेवारत रहने की सीख दी।

ये अधिकारी जिला प्रशिक्षण के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण, वन डिस्ट्रिक्ट - वन प्रोडक्ट, सोशल एंड फाइनेंशियल इन्क्लूजन, गुड गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, मैनेजमेंट जैसे विविध विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण से पूर्व ये अधिकारी चार सप्ताह के लिए स्पीपा अहमदाबाद में संस्थागत प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो 26 मई को पूर्ण होने वाला है।

मुख्यमंत्री से मिले इन प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारियों ने यह भावना भी व्यक्त की कि स्पीपा का प्रशिक्षण उनके करियर निर्माण में महत्वपूर्ण साबित हुआ है।

इस शिष्टाचार मुलाकात के दौरान स्पीपा के महानिदेशक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रधान सचिव श्री हारित शुक्ला, निदेशक श्री चंद्रेश कोटक तथा स्पीपा के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

भारत की रफ्तार को नई उड़ान: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की पहली झलक से बढ़ी उम्मीदें, हाई-स्पीड रेल युग की शुरुआत

नई दिल्ली। भारत के परिवहन इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। देश की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना Mumbai–Ahmedabad High Speed Rail Corridor (MAHSR) की पहली आधिकारिक झलक सोमवार को सार्वजनिक की गई, जिससे पूरे देश में उत्साह और चर्चा का माहौल बन गया है। रेल मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय के गेट नंबर-4 पर इस महत्वाकांक्षी परियोजना की तस्वीर प्रदर्शित की, जिसने भारत की भविष्य की रफ्तार की एक झलक पेश की है।

इस परियोजना को भारत की परिवहन क्रांति की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि यह देश की पहली बुलेट ट्रेन सेवा होगी, जो आधुनिक हाई स्पीड रेल तकनीक पर आधारित है। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है, जहां हाई स्पीड रेल नेटवर्क सफलतापूर्वक संचालित होता है।

रेल मंत्रालय के अनुसार, योजना है कि वर्ष 2026 के भीतर गुजरात में सूरत और बिलिमोरा के बीच लगभग 50 किलोमीटर के खंड में पहली बुलेट ट्रेन सेवा शुरू की जा सकती है। यह चरण भारत के लिए तकनीकी और परिचालन दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह पहली बार होगा जब देश में इतनी उच्च गति वाली रेल सेवा सार्वजनिक रूप से चलती नजर आएगी।

यह पूरी परियोजना लगभग 508 किलोमीटर लंबी है और इसे Mumbai–Ahmedabad High Speed Rail Corridor के नाम से जाना जाता है। यह कॉरिडोर महाराष्ट्र, गुजरात और दादरा एवं नगर हवेली से होकर गुजरता है, जिससे देश के पश्चिमी हिस्से के प्रमुख आर्थिक और औद्योगिक केंद्र आपस में और अधिक तेज़ी से जुड़ जाएंगे।

इस परियोजना की सबसे खास बात यह है कि इसे जापान की अत्याधुनिक शिंकान्सेन तकनीक के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। इस तकनीक को दुनिया में सबसे सुरक्षित और तेज़ रेल प्रणालियों में से एक माना जाता है। जापान ने न केवल तकनीकी सहयोग दिया है, बल्कि परियोजना के वित्तीय और इंजीनियरिंग ढांचे में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

रेल मंत्रालय और परियोजना से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू होने के बाद मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय वर्तमान की तुलना में काफी कम हो जाएगा। जहां अभी इस दूरी को तय करने में कई घंटे लगते हैं, वहीं हाई स्पीड रेल से यह सफर बेहद कम समय में पूरा किया जा सकेगा।

परियोजना से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल एक परिवहन साधन नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक संरचना को मजबूत करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसके जरिए व्यापार, पर्यटन और उद्योगों को नई गति मिलेगी। विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र जैसे औद्योगिक राज्यों के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।

इस परियोजना में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। ट्रैक डिजाइन से लेकर स्टेशन संरचना तक हर स्तर पर अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाया गया है। सुरक्षा, सिग्नलिंग सिस्टम और ट्रेन कंट्रोल तकनीक को भी पूरी तरह आधुनिक बनाया जा रहा है ताकि उच्च गति पर भी संचालन सुरक्षित रह सके।

परियोजना के तहत बनने वाले स्टेशन भी किसी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की तरह आधुनिक होंगे, जहां यात्री सुविधाओं, सुरक्षा जांच और डिजिटल सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह भारत में रेल यात्रा के अनुभव को पूरी तरह बदलने वाला कदम माना जा रहा है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस परियोजना के पूरा होने से लाखों रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। निर्माण, इंजीनियरिंग, तकनीकी रखरखाव और संचालन से जुड़े क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे। इसके अलावा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी यह परियोजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हाई स्पीड रेल के संचालन से सड़क और हवाई यातायात पर दबाव कम होने की उम्मीद है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आ सकती है। यह भारत के सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में भी एक अहम कदम माना जा रहा है।

परियोजना का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी गति है, जो इसे पारंपरिक रेल सेवाओं से पूरी तरह अलग बनाती है। जापानी शिंकान्सेन तकनीक की वजह से यह ट्रेन अत्यंत उच्च गति पर भी स्थिर और सुरक्षित रहती है। यही कारण है कि इसे दुनिया की सबसे भरोसेमंद रेल तकनीकों में गिना जाता है।

रेल मंत्रालय के अनुसार, परियोजना का कार्य विभिन्न चरणों में तेजी से आगे बढ़ रहा है और कई हिस्सों में ट्रैक बिछाने, पुल निर्माण और स्टेशन निर्माण का काम जारी है। सरकार का लक्ष्य है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर शुरुआती खंड को जनता के लिए खोल दिया जाए।

इस परियोजना को भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर इतिहास में एक "गेम चेंजर" माना जा रहा है, जो आने वाले दशकों में देश की परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह बदल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी नई दिशा देगा।

कुल मिलाकर, Mumbai–Ahmedabad High Speed Rail Corridor की पहली झलक ने देश में एक नए युग की शुरुआत का संकेत दे दिया है, जहां भारत अब सिर्फ पारंपरिक रेल नेटवर्क तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हाई स्पीड रेल के वैश्विक मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगा।

सोना वायदा में 829 रुपये, चांदी वायदा में 3775 रुपये और क्रूड ऑयल वायदा में 54 रुपये की वृद्धि

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 228926.87 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 38834.31 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 190092.44 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का मई वायदा 38500 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 3037.34 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 28170.21 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा सत्र के आरंभ में 158076 रुपये के भाव पर खूलकर, 159540 रुपये के दिन के उच्च और 157547 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 158547 रुपये के पिछले बंद के सामने 829 रुपये या 0.52 फीसदी की बढ़त के साथ 159376 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-गिनी मई वायदा 292 रुपये या 0.23 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 127693 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल मई वायदा 41 रुपये या 0.26 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 15999 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी जून वायदा 157690 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 159040 रुपये और नीचे में 157175 रुपये पर पहुंचकर, 737 रुपये या 0.47 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 158890 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन मई वायदा प्रति 10 ग्राम 157160 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 159221 रुपये और नीचे में 157159 रुपये पर पहुंचकर, 158404 रुपये के पिछले बंद के सामने 736 रुपये या 0.46 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 159140 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी जुलाई वायदा सत्र के आरंभ में 267400 रुपये के भाव पर खूलकर, 276764 रुपये के दिन के उच्च और 264949 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 271886 रुपये के पिछले बंद के सामने 3775 रुपये या 1.39 फीसदी की मजबूती के साथ 275661 रुपये प्रति किलो बोला गया। इनके अलावा चांदी-मिनी जून वायदा 4111 रुपये या 1.5 फीसदी बढ़कर 278948 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो जून वायदा 3973 रुपये या 1.45 फीसदी की तेजी के संग 278804 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

मेटल वर्ग में 3901.15 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मई वायदा 1.4 रुपये या 0.1 फीसदी बढ़कर 1343 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता मई वायदा 4.15 रुपये या 1.14 फीसदी की तेजी के संग 367.35 रुपये प्रति किलो हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम मई वायदा 2.4 रुपये या 0.63 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 381.25 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मई वायदा 55 पैसे या 0.27 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 202.8 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 38834.31 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 190092.44 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 28170.21 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 38500 पॉइंट के स्तर पर

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 6915.58 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मई वायदा सत्र के आरंभ में 10302 रुपये के भाव पर खूलकर, 10412 रुपये के दिन के उच्च और 10056 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 54 रुपये या 0.54 फीसदी की बढ़त के साथ 10134 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मई वायदा 45 रुपये या 0.45 फीसदी की मजबूती के साथ 10126 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस मई वायदा 290.4 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 295.4 रुपये और नीचे में 289.8 रुपये पर पहुंचकर, 284 रुपये के पिछले बंद के सामने 9.1 रुपये या 3.2 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 293.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मई वायदा 9.1 रुपये या 3.21 फीसदी की मजबूती के साथ 293 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मई वायदा सत्र के आरंभ में 994.8 रुपये के भाव पर खूलकर, 2.2 रुपये या 0.22 फीसदी गिरकर 997.6 रुपये प्रति किलो हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 12663.24 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 15506.97 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 2808.82 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 409.48 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 8.70 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 661.00 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 4636.19 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2263.42 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 2.96 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 10364 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 63605 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 19791 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 270930 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 42992 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 9338 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 22399 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 73416 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 20451 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 32751 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स मई वायदा सत्र के आरंभ में 38500 पॉइंट पर खूलकर, 38500 के उच्च और 38500 के नीचले स्तर को छूकर, 58 पॉइंट घटकर 38500 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जून 11000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 16.5 रुपये की गिरावट के साथ 387.6 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मई 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.75 रुपये की बढ़त के साथ 5.05 रुपये हुआ।

सोना मई 170000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 28 रुपये की गिरावट के साथ 245.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 558 रुपये की बढ़त के साथ 2400 रुपये हुआ। तांबा मई 1400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.14 रुपये की गिरावट के साथ 3.3 रुपये हुआ। जस्ता मई 410 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 3 पैसे की नरमी के साथ 0.45 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जून 8000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 30.6 रुपये की गिरावट के साथ 166.1 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मई 290 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 5.15 रुपये की गिरावट के साथ 7 रुपये हुआ। सोना मई 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 65 रुपये की गिरावट के साथ 369 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 220000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1 रुपये की बढ़त के साथ 376 रुपये हुआ। तांबा मई 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 16 पैसे की नरमी के साथ 5.99 रुपये हुआ। जस्ता मई 360 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2.73 रुपये की गिरावट के साथ 1.21 रुपये हुआ।